(b) The total length is 155 nautical miles (287 Kilometers). The ports are:—

1. Majali
2. Karwar including Sadashivgad
3. Binge
4. Chendia
5. Belikeri
6. Ankola
7. Gangawali.
8. Tadri
9. Kumta.
10. Honavar
11. Manki
12. Murdeshwar
13. Shirali
14. Bhatkal
15. Byndoor
16. Coondapur
17. Hangarkatta
18. Malpe
19. Mangalore

(c) The information is covered in reply to part (a).

(d) and (e). The first stage development of Karwar Port had been taken up by the State Government during the Third Plan as programmed. The State Government has prepared a project report for the second stage development of Karwar. The cost of developing Karwar as an all-weather port is estimated at Rs. 2 crores. The State Government have proposed that provision should be made in the Central Sector of the Fourth Five Year Plan for the development of Karwar, including the provision of mechanical ore handling equipment. The proposals relating to the Fourth Plan for intermediate and minor ports are being finalised.

In regard to Mangalore (existing port) certain schemes included in the Central Sector were dropped by the State Government in order to accommodate other priority schemes regarding minor ports. A new major port at Mangalore (Panambur) is also being developed and is expected to be completed by 1971.

Issue Prices of imported Wheat and Milo

2601. Shri D. C. Sharma: Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state:

(a) whether it has been decided to increase the issue price of imported wheat and milo;

(b) whether it is also proposed to increase the issue price of rice; and

(c) the extent to which the prices have been increased and the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Govinda Menon): (a) Yes, Sir. The issue prices of imported wheat and milo supplied from Central stocks have been raised with effect from 15-11-66.

(b) The question of revising the issue price of rice is under consideration of the Government.

(c) The issue prices of wheat and milo have been raised by Rs. 5.00 and Rs. 7.00 per quintal respectively. The increases have been necessitated in order to narrow down the gap between the low price of imported foodgrains and the price of indigenous foodgrains and also to reduce the amount of subsidy being borne by the Central Government.

भारत-तिब्बत सीमा पर चावल का चोरी छिपे लाना ले जाया जाना

2602. श्री शिंकरे :
श्री यु० द० सिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-तिब्बत सीमा पर कुछ व्यापारी तिब्बत में चोरी-छिपे चावल ले जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात का पता है कि इसमें कुछ सरकारी अधिकारियों का भी हाथ है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

सूखा से प्रभावित क्षेत्रों में नलकूप

2603. **श्री शिंकरे :**
श्री य० द० सिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने सूखा से प्रभावित क्षेत्रों में नलकूप लगाने की व्यवस्था की है;

(ख) यदि हां, तो 1 अक्तूबर, 1966 से लेकर आज तक कितने नलकूप लगाये गये हैं और कितने नलकूपों के लिए बिजली दी गई है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा अब तक पृथक्-पृथक् कितनी राशि नलकूप लगाने में खर्च की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्याम धर मिश्र) : (क) राज्य में सूखे की स्थिति का मुकाबला करने के लिए राज्य सरकार ने 90 अतिरिक्त गहरे नलकूप, 3000 अतिरिक्त कम गहरे नलकूप तथा 30,000 अतिरिक्त बोर एवं डग कुएं तैयार करने की योजना तैयार की है । सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में गहरे नलकूप खोदने के लिए समन्वेषी नलकूप संगठन के 2 रिगों को भेजने की व्यवस्था की गई है । कम गहरे नलकूपों तथा बोर एवं डग-कुंओं के लिए राज्य सरकार देसी मंडियों से अतिरिक्त हस्त-बोरिंग संयंत्रों तथा हल्की परकुशन रिगों को प्राप्त कर रही है । कुछ रिग खरीदी भी जा चुकी हैं । विदेशों से रिगों का आयात करने के लिए भी तुरन्त व्यवस्था की जा रही है ।

(ख) जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) उत्तर प्रदेश में लघु सिंचाई के लिए 2,130 लाख रुपये मंजूर किये गये थे । इसी प्रकार देहात में बिजली लगाने के लिए 900 लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी । भारत सरकार ने लघु सिंचाई तथा देहात में बिजली लगाने के अतिरिक्त कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिए राज्य सरकार को निम्न लिखित अतिरिक्त सहायता दी है :—

	रुपये
(1) गहरे नलकूपों का निर्माण, मरम्मत तथा पानी के लिए नालियों का निर्माण	150 लाख
(2) कम गहरे कुएं तथा डग कुओं का निर्माण	335 लाख
(3) नदियों तथा नहरों पर पम्प सेट लगाना	25 लाख
(4) नलकुओं पर बिजली लगाना तथा पम्प सेट लगाना	600 लाख
	1,110 लाख

Collision of Indian Ship with Liberian Tanker

2604. **Shri Brij Basi Lal:**
Shri Vishwa Nath Pandey:
Shri Braj Bihari Mehrotra:
Shri Ram Swarup:
Shri Balgovind Verma:

Will the Minister of **Transport, Aviation, Shipping and Tourism** be pleased to state: